शहडोल संभाग में इंसानी जिंदगी से खिलवाड़ का महाघोटाला!

डिग्रियां किराए पर, दवाएं नौसिखियों के हाथ

ड्रग इंस्पेक्टर की सेटिंग से फल-फूल रहा मौत का धंधा

शहडोल।

संभाग के तीनों जिलों शहडोल, अनूपपुर, उमरिया में आम जनता के स्वास्थ्य और जिंदगी को दांव पर लगाकर दवाओं के नाम पर सफेद जहर बेचने का एक बहुत बड़ा और संगठित गोरखधंधा खुलेआम चल रहा है। औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 के कड़े प्रावधानों की धज्जियां उड़ाते हुए संभाग के अधिकांश मेडिकल स्टोर बिना किसी अधिकृत फार्मासिस्ट के, सिर्फ और सिर्फ किराए की डिग्रियों के दम पर संचालित हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि दुकानों के भीतर केवल कागजी डिग्रियां और लाइसेंस दीवारों पर टंगे नजर आते हैं, जबकि काउंटर पर बैठकर गंभीर से गंभीर बीमारियां की दवाएं बांटने वाले लोग पूरी तरह नौसिखिए और अप्रशिक्षित हैं। इस जानलेवा खेल की पूरी पटकथा ड्रग विभाग और स्थानीय प्रशासन की सरपरस्ती में लिखी जा रही है।

5 से 8 हजार में बिक रहा ईमान

नियमों के मुताबिक, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की प्रत्यक्ष मौजूदगी के बिना किसी भी दवा दुकान से एक भी गोली नहीं बेची जा सकती। लाइसेंस जारी करते वक्त फार्मासिस्ट से बकायदा कोर्ट का शपथ-पत्र (एफिडेविट) लिया जाता है कि वह इस दुकान के अलावा कहीं और काम नहीं करेगा। लेकिन शहडोल संभाग में चल रहे सिंडिकेट ने इस नियम का मखौल बना दिया है। बेरोजगार या लालची फार्मासिस्ट महज 5 से 8 हजार रुपये प्रति महीने के लालच में अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन रसूखदार दुकान संचालकों को किराए पर सौंप देते हैं। गजब तो यह है कि यह सर्टिफिकेट धारक फार्मासिस्ट खुद किसी दूसरी दवा कंपनी या निजी अस्पताल में नौकरी कर रहा होता है और एक ही समय पर दो-दो जगहों से वेतन डकार रहा होता है। कानून की आंखों में धूल झोंकने का यह खेल बिना विभागीय सांठगांठ के मुमकिन नहीं है।

धनपुरी से बुढ़ार तक नियमों का जनाजा

इस गोरखधंधे की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा संभाग के कुछ उदाहरणों से लगाया जा सकता है। धनपुरी नंबर 3 में संचालित सांई मेडिकल के कर्ता-धर्ता ने अपनी दुकान कॉलरी से सेवानिवृत्त एक व्यक्ति को सौंप दी। स्टेट बैंक के पास स्थित इस दुकान के अलावा उक्त व्यक्ति ने केंद्रीय चिकित्सालय धनपुरी मोड़ पर भी एक और दवा दुकान लाइसेंस समेत खरीद ली। आज इन दोनों ही दुकानों पर बिना किसी योग्य फार्मासिस्ट के, कम पढ़े-लिखे कर्मचारी धड़ल्ले से दवाइयां बेच रहे हैं। ऐसा ही एक और कारनामा बुढ़ार में देखने को मिला है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की रोगी कल्याण समिति द्वारा बनाए गए कॉम्प्लेक्स में शासकीय आदेशों और अनुबंधों की स्पष्ट शर्तों के विपरीत जाकर दवा दुकानें खोलने की अवैध अनुमति दे दी गई। अनूपपुर और उमरिया जिला मुख्यालयों सहित ग्रामीण अंचलों में यह खेल बेधडक़ जारी है।

जल-पान कर लौट जाता है अमला

दवाइयों के इस अवैध कारोबार से आम जनता की जान आफत में है, लेकिन ड्रग विभाग और स्वास्थ्य अधिकारियों को जनहित से कोई सरोकार नहीं है। नाम न छापने की शर्त पर कुछ मेडिकल संचालकों ने दबी जुबान में कुबूल किया है कि ड्रग इंस्पेक्टर के नाम पर समय-समय पर मोटी रकम वसूली जाती है। औचक निरीक्षण के नाम पर कभी-कभार आने वाला जांच अमला दुकानों पर बैठकर जल-पान (सुविधा शुल्क) लेता है और बिना किसी कानूनी कार्रवाई के फाइलों पर ऑल ओके लिखकर वापस लौट जाता है। इस पूरे मामले पर जब विभाग के मुखिया से बात करने की कोशिश की, तो पता चला कि साहब तो पर्दानशीं हैं, पहरों के बीच वातानुकूलित दफ्तरों में बैठते हैं। आम जनता या मीडिया के कर्णकटु फोन कॉल्स उन तक नहीं पहुंच सकते। गैर-जरूरी नंबरों को वे सीधे ब्लैकलिस्ट या बेलाइन रखना ही मुनासिब समझते हैं। इतनी मजाल किसकी जो इन हुजूरे आला को हकीकत का आईना दिखा सके।

मौत के इस सिंडिकेट पर कब चलेगा मुख्यमंत्री का चाबुक

चंद दिनों तक किसी मेडिकल स्टोर पर झाड़ू-पोछा या हेल्पर का काम सीखने वाले लडक़े आज खुद डॉक्टर बनकर लोगों को पर्चियां देखकर दवाएं थमा रहे हैं। गलत सॉल्ट (दवा) मिलने के कारण मरीजों की जान पर बन आ रही है। भोपाल में बैठे आला अधिकारियों और स्वास्थ्य मंत्री से संभाग की जनता यह सवाल पूछ रही है कि आखिर इन फर्जी और जुगाड़ू मेडिकल स्टोर्स को सील करने की हिम्मत कौन दिखाएगा? क्या इस महीना बांधने वाले भ्रष्ट तंत्र पर कभी सख्त दंडात्मक कार्रवाई होगी या फिर किसी बड़ी जनहानि के बाद ही प्रशासन की यह कुंभकर्णी नींद टूटेगी?

सब्जी बाड़ी में छिडक़ा सफेद जहर

तड़प-तड़प कर मरे आधा दर्जन गौवंश!

खुले में छोड़ा कीटनाशक युक्त पानी, आक्रोशित ग्रामीणों ने घेरा थाना

शहडोल। जिले के सिंहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिंहपुर-बोडरी मार्ग पर स्थित कटहा नाला के पास आज उस समय हडक़ंप मच गया और समूचा क्षेत्र आक्रोश की अग्नि में सुलग उठा, जब खेतों के पास आधा दर्जन से अधिक बेजुबान गौवंश मृत अवस्था में पाए गए। आरोप है कि क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रही कमर्शियल सब्जी फार्मिंग में उपयोग किए गए अत्यंत घातक एवं प्रतिबंधित रसायनों और कीटनाशकों ने इन बेजुबान जीवों की जान ली है। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में गौमाता की तड़प-तड़प कर हुई मौत से न केवल पशुपालकों की कमर टूट गई है, बल्कि पूरे इलाके में तनाव और भारी जनआक्रोश व्याप्त हो गया है।

सिंहपुर के कटहा नाला के पास भारी लापरवाही

खुले में बहाया रासायनिक पानी

जमीनी हकीकत और ग्रामीणों के संगीन आरोपों के मुताबिक, कटहा नाला के समीप सब्जी की खेती करने वाले एक रसूखदार किसान द्वारा अपनी फसल को बचाने के लिए खेतों में भारी मात्रा में जानलेवा कीटनाशक (पेस्टीसाइड) और रसायनों का छिडक़ाव किया गया था। घोर लापरवाही की पराकाष्ठा तो यह रही कि रासायनिक दवाओं से मिश्रित जहरीला पानी खुले में ही छोड़ दिया गया था। प्यास बुझाने के चक्कर में जैसे ही बेजुबान गौवंशों ने इस काल रूपी पानी को पिया, वे मौके पर ही तड़पने लगे और देखते ही देखते हेमराज पटेल, रुद्र बैगा, परवी बाई तथा राधा पटेल के मवेशियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

लीपापोती की तो उग्र होगा आंदोलन

हादसे की खबर जंगल की आग की तरह फैलते ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और गौरक्षक मौके पर इक_ा हो गए। बेजुबान मवेशियों के शव देखकर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। भारी आर्थिक नुकसान झेल रहे पीड़ित पशुपालकों और ग्रामीणों ने तत्काल सिंहपुर थाने का रुख कर आरोपी किसान के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई है और सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई व मुआवजे की मांग की है। हालांकि, पुलिस और पशु चिकित्सा विभाग हमेशा की तरह जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई का रोना रो रहे हैं।

इनका कहना है...

मामले की जानकारी मिली मामले की जांच की जा रही।
आशीष झरिया
थाना प्रभारी, सिंहपुर

दीनदयाल रसोई के माध्यम से सस्ता भोजन कराएं उपलब्धः कलेक्टर

जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक सम्पन्न

शहडोल। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह की अध्यक्षता में दीनदयाल रसोई योजनांतर्गत गठित जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक कलेक्टर कार्यालय के सोन सभागार में आयोजित की गई। कलेक्टर ने कहा कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित दीनदयाल रसोई योजना एक जनकल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब, श्रमिक, जरूरतमंद एवं असहाय लोगों को कम कीमत पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध

कराना है। योजना के अंतर्गत शहरों में संचालित रसोई केंद्रों पर लोगों को बहुत कम शुल्क में भरपेट भोजन दिया जाता है। उन्होंने कहा कि गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराएं। बैठक में रघुकुल सामाजिक सेवा एवं मानव कल्याण द्वारा लिए गए टेंडर को एक वर्ष और बढ़ाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष घनश्याम जायसवाल, मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रीमती आशा भंडारी सहित जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति के सदस्य उपस्थित रहें।

गंगा दशहरा महापर्व में आयोजित होगी विधित कार्यक्रम, बैठक सम्पन्न

शहडोल। संभागीय समन्वयक जन अभियान परिषद के भीम सिंह डामोर एवं जिला समन्वयक विवेक पाण्डेय के उपस्थिति में बजरंग ग्राम विकास समिति चन्नौडी सेक्टर क्रमांक 05 में गंगा दशहरा महापर्व के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने

संबंधित बैठक आयोजित की गई। संभागीय समन्वयक जन अभियान परिषद ने कहा कि 25 मई को आयोजित होने वाले गंगा दशहरा महापर्व में जल संरक्षण, जल स्त्रोतों की स्वच्छता, जल पूजन, कलश यात्रा, मंदिरों में प्रतिष्ठित मूर्तियों का पूजन एवं जलाभिषेक, रामायण कीर्तन तथा जनजागरूकता जैसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में जनप्रतिनिधियो, अधिकारियो एवं आमजनो को शामिल करें। उन्होंने कहा कि गंगा दषहरा पर्व में जिले के नागरिक बढ़ चढकर सहभागी बनें और जल के संरक्षण एवं संवर्धन में अपना योगदान दें। बैठक में प्रस्फुटन समिति के अध्यक्ष सचिन बैरिहा, भमला, नेमुहा, शाहपुर और सेमरिहा समितियों के सदस्य, बुढार ब्लॉक के नवांकुर संस्था के अध्यक्ष सचिन, बुढ़ार ब्लॉक के परामर्शदाता उपस्थित रहें।

आबकारी विभाग द्वारा मदिरा दुकानो का किया गया निरीक्षण

शहडोल।

कलेक्टर डॉ. केदार सिंह के निर्देशन पर जिले में ओवर रेटिंग की लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आबकारी विभाग के मैदानी अमले द्वारा शहडोल नगर के सोहागपुर, बस स्टैंड स्थित कंपोजिट मदिरा दुकान, बुढ़ार रोड स्थित शराब दुकान सहित अन्य दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विभागीय अधिकारियों ने दुकानों में रेट सूची, बिक्री व्यवस्था एवं ग्राहकों से बातचीत कर जानकारी ली तथा दुकानदारो को शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने एवं ओवर रेटिंग जैसी शिकायतें नहीं आने देने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान आबकारी निरीक्षक रजनीश त्रिपाठी सहित आबकारी विभाग के अन्य मैदानी अमला उपस्थित रहा।

प्रेक्षक ने विभिन्न मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण

पात्र व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में कराएं दर्ज, न रहें वंचितः प्रेक्षक

शहडोल। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय निकाय नगरीय एवं ग्रामीण के मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की निगरानी के लिए नियुक्त किए गए प्रेक्षक श्री नीरज दुबे ने नगर पंचायत जयसिंहनगर के वार्ड क्रमांक 13, 11, 9 एवं 4 एवं जनपद पंचायत जयसिंहनगर अंतर्गत ग्राम पंचायत कौवासरई, टेटका, देवरी मसीरा सहित अन्य मतदान केंद्रो का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के

दौरान मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य का अवलोकन कर मतदाता सूची में नाम जोडऩे, नाम विलोपित करने, संशोधन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रो की जानकारी संबंधित बीएलओ से प्राप्त की। उन्होंने कहा मतदाता पुनरीक्षण कार्य का बेहतर प्रचार-प्रसार कराएं जिससे कोई भी पात्र व्यक्ति अपने मतदाता सूची में नाम जोडऩे हेतु वंचित न रहें एवं प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि विगत एक वर्ष के भीतर मृतक व्यक्तियो की सूची प्राप्त कर उनका नाम विलोपित करें। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार श्रीमती सुषमा धुर्वे, लाइजनिंग ऑफिसर आनंद अग्रवाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें।

शहडोल में अमृत हरित महाअभियान के तहत अफसरों और मालियों की लगी क्लास

शहडोल। हर साल बरसात के मौसम में लाखों रुपये फूंककर केवल फोटो खिंचवाने और कागजी हरियाली दिखाने वाले लापरवाह तंत्र पर इस बार पहले ही नकेल कस दी गई है। नगर पालिका परिषद शहडोल द्वारा अमृत हरित महाअभियान के तहत पौधारोपण से पहले जमीन तैयार करने और वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण करने हेतु एक संभाग स्तरीय हाई-प्रोफाइल कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का सीधा और साफ मकसद उन अफसरों, कर्मचारियों और स्व सहायता समूह की महिलाओं के पेंच कसना था, जो अब तक पारंपरिक और बेतरतीब ढंग से पौधे रोपकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष घनश्याम जायसवाल, विशिष्ट अतिथि संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन आर.पी. मिश्रा तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती आशा जितेंद्र भंडारी ने साफ तौर पर चेताया कि इस बार हर एक पौधे का हिसाब रखा जाएगा।

पौधों को जिंदा रखने के लिए जमीन पर पसीना बहाएगी टीम

लाइव डेमोंस्ट्रेशन से खोली आंखें

कार्यशाला में विषय विशेषज्ञ और वन विभाग के एसडीओ संतोष कुमार शुक्ला ने दो टूक शब्दों में तकनीकी बारीकियों को समझाया कि बिना तैयारी के पौधे लगाना उनकी हत्या करने जैसा है। वहीं, स्टेट मॉनिटरिंग टीम के अशोक कुमार मिश्रा ने भोपाल से वर्चुअल जुडक़र वृक्षारोपण की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। मंच पर तब हडक़ंप मच गया जब विशेषज्ञ विवेक शर्मा ने बकायदा मिट्टी, खाद और गड्ढे का लाइव डेमोंस्ट्रेशन (जीवंत प्रदर्शन) देकर भ्रष्ट और ढर्रे पर चल रही पुरानी प्रणाली की धज्जियां उड़ा दीं।

लापरवाही पर सीधे नपेगी टीम

पीडीएमसी के रेजिडेंशियल इंजीनियर संजय राय ने स्पष्ट किया कि इस महाअभियान में अमृत मित्रों की भूमिका केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं होगी, बल्कि उनकी सुरक्षा और सिंचाई की पूरी जवाबदेही उनकी होगी। संभाग के विभिन्न निकायों से आए नोडल अधिकारियों, उद्यान प्रभारियों, मालियों और महिलाओं को निराई-गुड़ाई, खाद प्रबंधन और पानी देने के कड़े नियम सिखाए गए। सिटी मिशन मैनेजर सत्यकाम मिश्रा द्वारा संचालित इस कार्यशाला में उप यंत्री सुखेंद्र सिंह तोमर, मनोज श्रीवास्तव सहित पूरी टीम मुस्तैद रही। अब देखना यह है कि इस कड़े प्रशिक्षण के बाद शहडोल संभाग की धरती वाकई हरी-भरी होती है या फिर हर साल की तरह करोड़ों के पौधे फाइलों में ही दम तोड़ देते हैं।

खबर संक्षेप

पेट्रोल-डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें पेट्रोल पंप संचालकः प्रभारी कलेक्टर

उमरिया। वर्तमान भू-राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रभारी कलेक्टर अभय सिंह ने जिले में पेट्रोल एवं डीजल की निर्बाध और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार उमरिया जिले में संचालित सभी पेट्रोल एवं डीजल पंपों के प्रोपाइटर, संचालक, मैनेजर और विक्रेताओं को अपने पंपों पर पर्याप्त मात्रा में ईंधन का भंडारण बनाए रखना होगा, ताकि शासकीय वाहनों, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस बल तथा अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होने निर्देशित किया है कि सभी पेट्रोल पंप संचालक अपने-अपने डिस्पेंसिंग यूनिट (नोजल) से वितरण योग्य पेट्रोल एवं डीजल का आवश्यक आरक्षित स्टॉक आगामी आदेश तक सुरक्षित रखेंगे। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आरक्षित पेट्रोल एवं डीजल स्टॉक का विक्रय अथवा प्रदाय जिला प्रशासन की अनुमति के बाद ही किया जाएगा। उन्होने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

गंगा दशहरा के अवसर पर आयोजित किए जाऐंगे विभिन्न कार्यक्रम

उमरिया। अपर कलेटर एवं परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण प्रमोद कुमार सेन गुप्ता ने बताया कि 25 मई को गंगा दशहरा के अवसर पर नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नानुसार भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम जिले के प्रभारी मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित किया जाना है। कार्यक्रम के मुख्यतः दो अवयव होंगे। प्रथम अवयव के तहत व्यापक जन सहयोग से जल संरक्षण और सवंर्धन कार्यों का क्रियान्वयन एवं तत्पश्चात द्वितीय अवयव के तहत सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। प्रस्तावित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधिगणों यथा सांसद, विधायक और नगरीय निकायों, पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। जल संरक्षण और सवंर्धन कार्यों के क्रियान्वयन के लिए जन समुदाय, जन प्रतिनिधियों तथा अन्य संगठनों के सहयोग से सामुहिक श्रमदान और योगदान (उदाहरण के तौर पर मशीने, मशीनों हेतु ईधन, परिवहन इत्यादि) का नियोजन कर निम्न कार्य किये जायेगे । कुंओं, नहरों तथा पुरानी जल संग्रहण संरचनाओं जैसे बावड़ी और तालाब इत्यादि का जीर्णोद्धार तथा साफ सफाई कार्य , घाटों की साफ सफाई कार्य, पूर्व में निर्मित बोरवेल ट्यूबवेल (जिनका उपयोग भूजल दोहन हेतु होता था परन्तु वर्तमान में भूजल स्तर नीचे जाने से उपयोग में नहीं आ रहे हैं) पर रिचार्ज पिट का निर्माण अन्य जल संरक्षण संबंधी कार्य किए जाएगे । कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जन सहभागिता से जल संरक्षण और संरक्षण कार्यों का क्रियान्वयन करना है । गंगा दशहरा के अवसर पर सामूहिक श्रमदान,योगदान द्वारा जल संरक्षण और संवर्धन कार्यों के क्रियान्वयन में जन प्रतिनिधिगण, जिले में सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, गणमान्य नागरिकों, व्यापारिक और ओद्योगिक संगठनों स्वयं सेवी संगठनों, सामाजिक व धार्मिक संगठनों और सामुदायिक संगठनों जैसे महिला स्व सहायता समूहों इत्यादि की सहभागिता सुनिश्चित किया जाएगा । जिले में न्यूनतम 4 से 5 ऐसे कार्य क्रियान्वित किये जायें जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। कार्यक्रम के आयोजन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत तथा नगरीय क्षेत्र में परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास प्राधिकरण नोडल अधिकारी होंगे।

भोपाल मुख्यालय से दखल की मांग

शिकारी कुत्तों के हवाले बांधवगढ़ का कोर ज़ोन

सूखे सोसारों ने मौत के मुहाने पर बाघों को धकेला

उमरिया। विश्व प्रसिद्ध कान्हा टाइगर रिजर्व में केनाइन डिस्टेंपर वायरस (सीडीवी) के कहर से हुई बाघों की दर्दनाक मौत ने पूरे देश के वन्यजीव प्रेमियों को झकझोर कर रख दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर मचे इस हडक़ंप के बाद भी पड़ोसी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का प्रबंधन अपनी गहरी और लापरवाह नींद से जागने को तैयार नहीं है। पार्क के सबसे अति-सुरक्षित माने जाने वाले कोर ज़ोन की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह तार-तार हो चुकी है। बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर पर्यटकों द्वारा वायरल की जा रही तस्वीरें और वीडियो इस कड़वी हकीकत की गवाही दे रहे हैं, जिनमें स्थानीय गांवों के शिकारी कुत्ते पार्क के भीतर घुसकर हिरणों का शिकार करते साफ नजर आ रहे हैं। इन वायरल वीडियो ने न केवल नेशनल पार्क की सुरक्षा दावों की पोल खोल दी है, बल्कि अफसरों की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।

रेंजों में साइलेंट किलर को खुला न्योता

वन्यजीव विशेषज्ञों का स्पष्ट कहना है कि बांधवगढ़ प्रबंधन कान्हा की भयावह घटना से कोई सबक लेने को राजी नहीं है। यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इसी कातिल केनाइन डिस्टेंपर वायरस के संक्रमण के चलते बांधवगढ़ अपने कई बेशकीमती बाघों को असमय खो चुका है। यह जानलेवा और संक्रामक वायरस सीधे तौर पर पालतू और आवारा कुत्तों के जरिए ही जंगलों में पहुंचता है और बाघों व अन्य हिंसक वन्यजीवों को अपनी चपेट में ले लेता है। पार्क के सबसे संवेदनशील माने जाने वाले ताला, मगधी और खितौली रेंजों के कोर एरिया में इन आवारा शिकारी कुत्तों का बेधडक़ घूमना और शाकाहारी जीवों को अपना निवाला बनाना, यहाँ के बाघों के

लिए सीधे तौर पर डेथ वारंट जारी करने जैसा है।

बूंद-बूंद पानी को तरस रहे वन्यजीव

भीषण गर्मी के इस मौसम में पार्क के भीतर के हालात और भी बदतर हो चुके हैं। खबर है कि ताला और मगधी रेंज के भीतर बने अधिकांश वाटर होल्स (सोसारे) या तो पूरी तरह सूख चुके हैं या उनमें नाममात्र का कीचडयुक्त पानी बचा है। प्यास से बेहाल बेजुबान जानवर बूंद-बूंद पानी के लिए जंगलों में भटकने को मजबूर हैं। अपनी प्यास बुझाने की जद्दोजहद में ये वन्यजीव पार्क की सीमाओं को लांघकर रिहाइशी और ग्रामीण इलाकों की ओर भाग रहे हैं। वन्यजीवों की इसी मजबूरी और भटकाव का फायदा उठाकर गांवों के शिकारी कुत्ते कोर ज़ोन के भीतर तक घुसपैठ कर रहे हैं और वन्यजीवों को मौत के घाट उतार रहे हैं।

ले-देकर रफा-दफा हो रहे मामले

बांधवगढ़ में केवल सुरक्षा की ही भारी चूक नहीं है, बल्कि प्रशासनिक गलियारों से भ्रष्टाचार की भीषण दुर्गंध आ रही है। स्थानीय सूत्रों और जागरूक पर्यटकों के मुताबिक, मोटी रकम और रसूख (वीआईपी कल्चर) के दम पर पर्यटकों के वाहनों को खितौली और मगधी रेंज के उन प्रतिबंधित मार्गों पर धड़ल्ले से ले जाया जा रहा है, जहां वन्यजीवों की सुरक्षा और मानसिक शांति के लिए इंसानी आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध है। इन प्रतिबंधित इलाकों में मोटी रकम के एवज में रईस पर्यटकों को बाघों की क्लोज-अप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जा रही है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जब ये अवैध वीआईपी सफारी के मामले पार्क के आला अधिकारियों के कानों तक पहुंचते हैं, तो वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई या एफआईआर दर्ज करने के बजाय, बंद कमरों में ले-देकर पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। टेबल के नीचे से होने वाले इस सैटलमेंट ने जमीन पर ईमानदारी से ड्यूटी करने वाले फील्ड स्टाफ के हौसले पूरी तरह पस्त कर दिए हैं।

दफ्तरों के एसी में कैद अफसर

सफारी पर आने वाले जागरूक वन्यजीव प्रेमियों और स्थानीय निवासियों ने बांधवगढ़ के क्षेत्र संचालक और उनके सिपहसालारों पर घोर लापरवाही और निकम्मेपन का आरोप मढ़ा है। जमीनी हकीकत यह है कि ताला, मगधी और खितौली जैसी मुख्य रेंजों के मैदानी इलाकों में कोई भी जिम्मेदार बड़ा अधिकारी कभी गश्त करता नजर नहीं आता। वन्यजीवों की सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़, ये अफसर सिर्फ अपने वातानुकूलित केबिनों में बैठकर कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं।

भोपाल मुख्यालय तुरंत संभाले कमान

अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। बांधवगढ़ के बिगड़ते हालातों को देखकर स्थानीय पर्यावरणविदों और पर्यटकों ने सीधे वन्यप्राणी मुख्यालय, भोपाल से आपातकालीन हस्तक्षेप की मांग की है। वन्यजीव प्रेमियों की पुरजोर मांग है कि बांधवगढ़ की कमान तत्काल किसी संवेदनशील, कर्मठ और ईमानदार अधिकारी को सौंपी जाए। प्रतिबंधित रूटों पर गाडिय़ां घुसाने वाले जिप्सी चालकों और उन्हें शह देने वाले भ्रष्ट अधिकारियों व रेंजरों को तत्काल निलंबित किया जाए। वन्यजीवों को बचाने के लिए युद्धस्तर पर टैंकरों के माध्यम से सोसारों को भरा जाए। अगर समय रहते भोपाल मुख्यालय ने इस सफेद हाथी बन चुके प्रबंधन पर नकेल नहीं कसी, तो बांधवगढ़ को बाघों का कब्रिस्तान बनते देर नहीं लगेगी।

बरुहा नाला के पास दर्दनाक सड़क दुर्घटना

एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर

मानपुर। राजकीय राजमार्ग क्रमांक 10 (पनपथा-बरही मार्ग) पर स्थित ग्राम पंचायत पलझा के बरुहा नाला के पास भीषण सडक़ हादसे ने एक हंसते-खेलते परिवार का चिराग बुझा दिया। तेज रफ्तार दुपहिया वाहन के अनियंत्रित होकर मील के पत्थर से टकराने के कारण एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोपहर लगभग 12 बजे दुपहिया वाहन पर सवार होकर रघुवीर बर्मन उम्र 25 वर्ष और रामपाल सिंह गोंड निवासी पलझा कहीं जा रहे थे। तभी बरुहा नाला के समीप उनका वाहन अचानक अनियंत्रित हो गया और सीधे सडक़ किनारे लगे मील के पत्थर से जा टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक लहूलुहान होकर सडक़ पर गिर पड़े।स्थानीय ग्रामीणों की तत्परता से दोनों घायलों को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र अमरपुर ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने परीक्षण के उपरांत रघुवीर बर्मन

को मृत घोषित कर दिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल रामपाल सिंह की अत्यंत नाजुक हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें तत्काल कटनी चिकित्सा महाविद्यालय के लिए प्रेषित कर दिया गया, जहां वे वेंटिलेटर पर जीवन की जंग लड़ रहे हैं।

शराब दुकान हटाने वार्डवासियों द्वारा लगातार किया जा रहा विरोध

हरिभूमि न्यूज कोतमा। नगर के आबादी परिसर बस स्टैंड, स्टेट बैंक एवं बाजार क्षेत्र वार्ड 4 में स्थित शराब दुकान हटाने को लेकर वार्डवासियों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। शराब दुकान हटाने को लेकर वार्डवासियों द्वारा पूर्व मे जिला कलेक्टर, आबकारी विभाग, नगर पालिका सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को शिकायत करते हुए दुकान हटाने की मांग की गई थी।

लेकिन शराब दुकान हटाने को लेकर कोई कार्यवाही आज तक नहीं हो सकी आलम यह है की मुख्य मार्ग में संचालित शराब दुकान के सामने व आसपास लगी मीट एवं अंडे की दुकानों में बैठकर शराब का सेवन करते हैं और अश्लील गाली गलौज करते हुए देर रात तक हंगामा किया जाता है। जिससे वार्डवासी परेशान रहते है। बस स्टैंड के पास शराब दुकान होने की वजह से देर रात तक राहगीर एवं नागरिकों का आना-जाना बना रहता है जो कि इन नशाखोरों की गाली गलौज एवं अभद्र भाषण से शर्मसार होने को मजबूर रहते हैं। शराब दुकान के कारण ही एक दर्जन से ज्यादा ठेले की दुकान होने के कारण शराबी वहीं बैठकर शराब का सेवन करते हैं और सड़क में ही खाली बोतल व मीट की हड्डी फेक दिये जाने से लोगों में जमकर नाराजगी बनी रहती है। नागरिकों एवं वार्डवासियों द्वारा सैकड़ो की संख्या में कई बार मंत्री दिलीप जायसवाल से मिलकर होने वाली गतिविधियों व परेशानी को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए शराब दुकान हटाए जाने की मांग भी की जा चुकी है। लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा दुकान हटाने संबंधी कार्यवाही नहीं कर रही है। लोगों का कहना है कि शराब दुकान के कारण शाम ढलते हो शराबखोरी एवं हंगामा शुरू हो जाता है जो देर रात जारी रहता है। शराब दुकान के कारण व्यापार भी प्रभावित हो रहा दूसरी ओर घर की महिलाएं बाहर नहीं निकल पा रही। नागरिकों ने जिला प्रशासन एवं आबकारी विभाग से रिहायशी क्षेत्र से शराब दुकान हटाने एवं शराब दुकान के पास खुले अवैध शराब के अड्डों पर कार्यवाही की मांग की गई है।

जन प्रतिनिधियों से टूटता जा रहा नागरिकों का विश्वास, आस हो रही खत्म

कोयलांचल क्षेत्र के साथ रेल प्रबंधन के द्वारा किया जा रहा सौतेला व्यवहार

कोतमा। नगर में सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है जबकि कोतमा विधानसभा क्षेत्र से ही संभाग के इकलौते मंत्री दिलीप जायसवाल प्रदेश में मंत्री के पद पर आसीन है। कहने को तो शहडोल संसदीय क्षेत्र से हिमाद्री सिंह सांसद हैं और उनके ही संसदीय क्षेत्र में लोग ट्रेनों को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। लोग अब तो सांसद पर सवालिया निशान भी खड़ा करने लगे हैं कि आए दिन सांसद के द्वारा क्षेत्र की रेल समस्याओं को लेकर रेल मंत्री से मुलाकात करते हुए मांग पत्र सौपा जाता है लेकिन यह मांग पत्र मांग पत्र ही बनकर रह जाती है दूसरा कार्यकाल शुरू है उनका लेकिन रेल सुविधाओं के नाम पर इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है यह लोगों के बीच अब जन चर्चा का विषय बनकर रह गया है। वही लोग अब चौक चौराहों में खड़े होकर यह चर्चा भी कर रहे हैं कि हमारे यहां के सांसद से तो अच्छे छत्तीसगढ़ के सांसद है जिनकी मांगों पर रेल प्रबंधन के द्वारा तत्काल विचार करते हुए मांग स्वीकृत कर दिया जाता है साथ ही वर्तमान मे जो विकास रीवा का हो रहा है चाहे वह ट्रेन की सुविधा हो या एयरपोर्ट की और इन्हें आए दिन ट्रेनों की सौगातें भी मिलने लगी है। नागपुर तक सीधी ट्रेन चलाये जाने की मांग बर्षो से की जा रही है लेकिन उस पर आज तक रेलवे प्रबंधन के द्वारा विचार नही किया जा रहा है। कोरोना काल के समय से चिरमिरी रीवा ट्रेन को सप्ताह मे तीन दिन कर दिया गया जबकि यह नियमित ट्रेन थी आज तक उसे प्रतिदिन नही किया गया। अनूपपुर जिले का सबसे बड़ा शहर कोतमा है और इसके साथ ही रेल प्रबंधन के द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। नगर के उद्योग एवं व्यवसायिक संगठन के द्वारा पूर्व मे छत्तीसगढ़ के सांसद बृजमोहन अग्रवाल पर भरोसा जताते हुए उनको एक मांग पत्र भेजा था जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि सरगुजा संभाग एवं शहडोल संभाग के यात्रियों की सुविधा हेतु रेल प्रबंधन से विभिन्न मांगों के संबंध में यह मांग पत्र सौपा गया है। उद्योग व व्यवसायिक संघ कोतमा के द्वारा मांग पत्र में उल्लेख किया गया था कि सरगुजा संभाग एवं शहडोल संभाग आदिवासी पिछड़ा बाहुल्य क्षेत्र है। रेल विभाग द्वारा यहां पर किसी भी प्रकार की नई ट्रेनों की सुविधा तथा पुरानी सुविधा जो भी थी उन्हें भी कोरोना काल में बंद कर दिया गया। जबकि इन दोनों संभागों से रेलवे को काफी आय होती है क्योंकि पूरे क्षेत्र में कोयले की ढुलाई की जाती है इसके एवज में रेलवे नाम मात्र का खर्च करता है। इस क्षेत्र की उपेक्षा निरंतर हो रही है। कोतमा उद्योग व्यवसायिक संघ के द्वारा छत्तीसगढ़ के सांसद बृजमोहन अग्रवाल को मांग पत्र देते हुए उल्लेख किया है कि ट्रेन नंबर 18242 और 18243 अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस को नागपुर तक बढ़ाया जाए इस संभागों के मरीज को इलाज के लिए नागपुर के लिए सीधी ट्रेन ना होने के कारण बिलासपुर अथवा कटनी से ट्रेन पकड़नी पड़ती है इसे अंबिकापुर से 2 घंटे पूर्व छोडा. जाए एवं अंबिकापुर शहडोल ट्रेन को बंद कर दिया जाए। चिरमिरी बिलासपुर ट्रेन को जिसका गाड़ी संख्या 18258 को चिरमिरी से झारसुगड़ा या रायगढ़ तक बढ़ाया जाए क्योंकि वह सुबह 4:30 बजे बिलासपुर पहुंचकर दिनभर बिलासपुर स्टेशन में खड़ी रहती है और फिर रात को चलती है। ट्रेन नंबर 18202 शहडोल नागपुर एक्सप्रेस को अंबिकापुर से नागपुर चलाया जाए ताकि अनूपपुर जिले के साथ ही सरगुजा संभाग के यात्रियों को स्वास्थ्य लाभ के लिए नागपुर जाने के लिए सीधी ट्रेन उपलब्ध हो सके यह ट्रेन अभी शहडोल से चलती है इसे बालाघाट गोंदिया रूट से चलाया जाता है।

हरिभूमि न्यूज कोतमा। नागरिकों की आस अब हो रही खत्म, नागरिकों का विश्वास अब जनप्रतिनिधियों से टूटता जा रहा है। कोयलांचल एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ रेल प्रबंधन के द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। यहां के लोगों को ट्रेन सुविधा के नाम पर मात्र झुनझुना पकड़ा दिया जाता है जबकि इस क्षेत्र में कई कोयला की खदानें संचालित है। और यह क्षेत्र वन संपदा से भी आच्छादित है। वर्तमान मे कई उद्योग खुलने वाले हैं लेकिन ट्रेन की सुविधा पर्याप्त न होने के कारण यहां का व्यापार भी ठप्प होते जा रहा है।

अंबिकापुर से मुंबई के लिए ट्रेन चलाई जाए ताकि दोनों संभागों के लोगों को इसका लाभ मिल सके। चिरमिरी रीवा गाड़ी संख्या 11752 तथा रीवा चिरमिरी को कोरोना काल की पूर्व स्थिति में बहाल किया जाए पूर्व में यह ट्रेन सातों दिन चलती थी वर्तमान में तीन दिन ही चल रही है। अनूपपुर मनेंद्रगढ़ मेमू ट्रेन जो की अनूपपुर जंक्शन से मनेद्रगढ़ के लिए रात्रि 10:15 पर रवाना होती है इसमें किसी भी ट्रेन का मिलन ना होने के कारण पूरी ट्रेन खाली जाती है इस ट्रेन को रात्रि 12:00 बजे अनूपपुर जंक्शन से रवाना किया जाए जिससे अमरकंटक एक्सप्रेस की सवारी तथा कटनी मार्ग से जाने वाली ट्रेनों की सवारी अपने गंतव्य को जाने के लिए कनेक्टिविटी मिल सके। प्लेटफार्म मे डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाय जिससे यात्रियों को अपने निर्धारित कोच मे चढ़ने मे आसानी हो। स्टेशन में महिला या पुरुष के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है वार्ड 14, 15 रेलवे ओवरब्रिज पर सोलर लाइट या विद्युत लाइट की व्यवस्था प्लेटफार्म एक और दो दोनों सेट से पानी अंदर गिरता है उसकी रिपेयरिंग की व्यवस्था एवं ठंडा पानी पीने की व्यवस्था करवाई जाए। कई नई साप्ताहिक ट्रेनें चलाई गई है उन ट्रेनों का स्टॉपेज भी कोतमा में नहीं दिया गया है जिसके कारण आम नागरिकों के साथ ही व्यापारी परेशान हो रहे हैं।

पूर्व विधायक मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि हमारा क्षेत्र काफी पिछड़ा क्षेत्र है और यहां सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है रेल प्रबंधन के द्वारा भी इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। नागपुर के लिए सीधी रेल सेवा आज समय की जरूरत बन चुकी है। अंबिकापुर से नागपुर वाया बिजुरी, कोतमा, अनूपपुर कोयलांचल क्षेत्र के लिए सीधी रेल सेवा की सुविधा प्रदान की जाये। कोयलांचल क्षेत्र के यात्रियों को अब भी लंबा और असुविधाजनक सफर तय करना पड़ता है। शहडोल-नागपुर एक्सप्रेस का विस्तार अंबिकापुर तक करके अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस को नागपुर तक विस्तार करके अंबिकापुर-नागपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, चिरमिरी- बिलासपुर एक्सप्रेस का विस्तार नागपुर तक करके कोयलांचल क्षेत्र वासियों को सीधा नागपुर से जोड़ा जा सकता है। जिससे हजारों यात्रियों को सीधी ट्रेन की सुविधा मिल सके। लाखों लोगों को बेहतर ईलाज के नागपुर लिए सीधा साधन मिल सके। व्यापार और रोजगार को इससे बढ़ावा मिल सकेगा। बर्षो से नागरिकों के द्वारा मांग की जा रही है लेकिन सीधी ट्रेन की सुविधा का लाभ आज तक नही मिल पा रहा है।

कोतमा उद्योग व्यवसायिक संगठन के कार्यवाहक अध्यक्ष विनोद कुमार सराफ का कहना है कि हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर से सांसद बृजमोहन अग्रवाल जो की एसईसीआर में सलाहकार सदस्य भी है उन्हें हमारे द्वारा ट्रेनों से संबंधित मांग पत्र भेजा गया था। हमारे क्षेत्र के साथ रेल प्रबंधन सौतेला व्यवहार कर रहा है हमारे यहां से सांसद हिमाद्री सिंह के द्वारा कई बार रेल मंत्री से मुलाकात कर ट्रेनों के संबंध में चर्चा करते हुए मांग पत्र भी दिया गया है लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है जबकि छत्तीसगढ़ के सांसदों के द्वारा ट्रेनों से संबंधित जो भी मांग पत्र सोपा जाता है उस पर विचार करते हुए तत्काल ही रेल प्रबंधन के द्वारा अमल किया जाता है।

सराफा व्यवसाई अंकुश सोनी जानी का कहना है कि हमारा नगर जिले का सबसे बड़ा व्यवसायिक क्षेत्र है और यहां पर कई कोयले की खदानें संचालित है उसके बावजूद रेल प्रबंधन के द्वारा इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है पूर्व में जो ट्रेन संचालित थी उन्हें भी अस्त-व्यस्त कर दिया गया है। जिसका रीव चिरमिरी ट्रेन की नियमित सुविधा थी जिसे भी सप्ताह मे तीन दिन कर दिया गया जिसे आज तक रेलवे प्रबंधन के द्वारा नियमित नही किया जा रहा है। जबकि हम व्यापारियों को व्यापार के लिए बाहर जाना पड़ता है। हमारे यहां के सांसद से यहां के लोगों की काफी उपेक्षाएं थी लेकिन उसमें भी वह खरी नहीं उतर रही है उनके द्वारा अभी तक हमारे क्षेत्र को कोई भी ट्रेन की सुविधा नहीं दिलवा पाई जबकि उनके द्वारा आए दिन सोशल मीडिया में रेल मंत्री के साथ मुलाकात करते हुए मांग पत्र सौपने की तस्वीर सामने आती है।

कंप्यूटर व्यवसाई अमित सैनी का कहना है कि हमारे क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है हमारे यहां ना तो सही ढंग से स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाई जा रही है और ना ही ट्रेन की सुविधा दी जा रही है जबकि यहां के लोगों को इलाज के लिए आए दिन नागपुर जाना पड़ता है सीधी ट्रेन नहीं होने के कारण लोगों को आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है अंबिकापुर से नागपुर तक सीधी ट्रेन चलवाई जाए अंबिकापुर से मुंबई तथा अम्बिकापुर से प्रयागराज के लिए सीधी ट्रेन की सुविधा प्रदान की जाये जिससे यहां के लोगों को बाहर आने जाने के लिए सीधी ट्रेन की सुविधा मिल सके।

खबर संक्षेप

पिंजरा तोड़कर भागा हाथीः केशवाही में रेस्क्यू के दौरान मची भगदड़.

शहडोल। जिले के केशवाही वन परिक्षेत्र के बेलिया जंगल में शुक्रवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया और मौत का सन्नाटा पसर गया, जब पिछले चार दिनों से वन विभाग को छका रहा एक बिगड़ैल आदमखोर हाथी पिंजरा तोड़कर दोबारा घने जंगलों की ओर भाग निकला। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक बहुत बड़ा हादसा होते-होते टला। हाथी के अचानक रौद्र रूप धारण करते ही मौके पर मौजूद बांधवगढ़ और संजय गांधी टाइगर रिजर्व के आला अधिकारियों, डॉक्टरों और दो दर्जन से अधिक मैदानी कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई और सबने भागकर बमुश्किल अपनी जान बचाई।

पिंजरे में पैर रखते ही फूटा गुस्सा

वन अमले ने बिगड़ैल हाथी को घेरने के लिए चार प्रशिक्षित कुमकी हाथियों का सहारा लिया था। चक्रव्यूह रचकर हाथी को बेलिया स्थित कैंप तक लाया भी गया, लेकिन जैसे ही उसे पिंजरे के भीतर धकेला गया, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने लोहे और लकड़ी के भारी-भरकम पिंजरे को एक झटके में खिलौने की तरह पलटकर क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथी को काबू में करने के लिए रेस्क्यू टीम ने एक के बाद एक तीन बार ट्रैंकुलाइजर गन से बेहोशी का तगड़ा डोज (निशाना) दागा, लेकिन आदमखोर पर इन दवाओं का कोई असर नहीं हुआ और वह चिंघाड़ता हुआ पिंजरे के परखच्चे उड़ाकर दोबारा लापता हो गया। टूटे हुए पिंजरे को मरम्मत के लिए बुढार भेजा गया है।

जैतपुर में दिनदहाड़े नदियों का सीना चीर रहे हाइवा

शहडोल। जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र में कानून-व्यवस्था और खनिज विभाग की नाक के नीचे अवैध रेत उत्खनन और परिवहन का महाघोटाला खुलेआम फल-फूल रहा है। सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह वायरल हुए एक सनसनीखेज वीडियो ने इस पूरे काले कारोबार और प्रशासनिक साठगांठ की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। वायरल वीडियो में रेत से आकंठ भरे एक हाइवा के चालक और परिचालक सरेआम कैमरे के सामने यह कबूल करते नजर आ रहे हैं कि यह अवैध रेत गलहथा घाट से चुराकर लाई गई है। सबसे बड़ा और यक्ष प्रश्न यह है कि जब पूरे शहडोल जिले में किसी भी रेत खदान का कोई वैध ठेका संचालित ही नहीं है, तो फिर किसकी शह पर ये यमदूत बने भारी वाहन जैतपुर नगर के बीचों-बीच से बेधडक़ गुजर रहे हैं? स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा अब सातवें आसमान पर है। गाड़ाघाट और गलहथा समेत आधा दर्जन घाटों पर दिन-रात माफियाओं की पोकलेन और जेसीबी मशीनें नदियों का सीना छलनी कर रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी खनिज विभाग और जैतपुर पुलिस कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। इस पूरे खेल में जैतपुर थाने में पदस्थ यादव नामक एक आरक्षक की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जिसका नाम पहले भी रेत के इस काले सिंडिकेट को संरक्षण देने में उछल चुका है। माफियाओं का नेटवर्क इतना शातिर है कि जब जनआक्रोश बढऩे पर पुलिस या खनिज अमला मजबूरी में किसी वाहन पर हाथ डालता है, तो वाहन मालिक तत्काल पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की खदानों की रॉयल्टी पर्ची (टीपी) का जुगाड़ कर पेश कर देते हैं। मध्य प्रदेश की नदियों से रेत चोरी कर छत्तीसगढ़ की पर्ची पर उसे वैध दिखाने का यह खेल बिना बड़े अफसरों के आशीर्वाद के मुमकिन नहीं है। इस अंधाधुंध अवैध उत्खनन से सोन नदी और उसकी सहायक नदियों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है, लेकिन जिम्मेदार विभाग गांधारी बने तमाशा देख रहे हैं। क्या भोपाल में बैठे आला अधिकारी इस संगठित लूट पर नकेल कसेंगे या जैतपुर को इसी तरह रेत माफियाओं के हवाले छोड़ दिया जाएगा।

इनका कहना है...

अगर जैतपुर क्षेत्र से रेत निकल रही है, तो वह अवैध है,क्यों कि जिले में अभी रेत खदानों ठेका नहीं हुआ है। मुझे शिकायत मिली है कि जैतपुर के गलहथा और गाड़ाघाट और लुकमपुर से रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। हम कारवाही करेंगे। कुछ वाहन उधर छत्तीसगढ़ से वैध रेत लाते है। हम उसकी भी जांच करेंगे।

राहुल शांडिल्य
जिला खनिज अधिकारी

उमरिया में बना हाई-टेक विशेष प्रकोष्ठ

अब कचरा माफिया और लापरवाह अफसरों की खैर नहीं

कलेक्टर राखी सहाय की अध्यक्षता में स्पेशल सेल का गठन
सर्वोच्च न्यायालय के डंडे के बाद जागा प्रशासन
हर महीने खुलेगा विकास का कच्चा चिट्ठा

उमरिया। जिले को गंदगी और अवैध डंपिंग यार्ड के कलंक से मुक्ति दिलाने के लिए आखिरकार प्रशासन को कड़ा कदम उठाना ही पड़ा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के कड़े क्रियान्वयन और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर (19 फरवरी, 29 अप्रैल और 5 मई 2026) फटकार स्वरूप जारी किए गए सख्त निर्देशों के अनुपालन में जिला कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय की अध्यक्षता में एक शक्तिशाली विशेष प्रकोष्ठ (स्पेशल सेल) का गठन कर दिया गया है। यह हाई-टेक सेल आगामी एक वर्ष तक जिले की सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सीधे हंटर चलाएगा। इस विशेष समिति में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभय सिंह को सदस्य सचिव और मुख्य समन्वयक की कमान सौंपी गई है, जबकि जिले के तमाम आला अधिकारियों को इस सेल में शामिल कर जवाबदेही तय की गई है।

वर्चुअल मॉनिटरिंग से उड़ेगी लापरवाहों की नींद

कागजों पर साफ-सफाई का ढिंढोरा पीटने वाले नगर पालिकाओं और जनपद पंचायतों के दिन अब लद चुके हैं। इस विशेष प्रकोष्ठ की सबसे धारदार रणनीति यह है कि अब जिले के सभी डंपिंग साइट्स (कचरा फेंकने के स्थानों) का वर्चुअल निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे जिले में चल रहे अवैध और अनधिकृत डंप साइटों की जमीन पर जाकर शिनाख्त करें और उनकी तस्वीरें व रिपोर्ट सीधे समिति के सामने पेश करें। अब टेबल के नीचे से फाइलें पास कराने का खेल नहीं चलेगा, हर 15 दिन में प्रगति रिपोर्ट सीधे राज्य सरकार की मेज पर होगी।

कचरा वीआईपी का खेल खत्म

बांधवगढ़ जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और धार्मिक तीर्थ स्थलों पर अब गंदगी फैलाने वालों की खैर नहीं होगी। विशेष प्रकोष्ठ इन संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों के लिए एक विशेष क्विक रिस्पॉन्स तंत्र विकसित करने जा रहा है। इसके साथ ही, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 की धज्जियां उड़ाने वालों पर भारी जुर्माने की तैयारी है। ग्रामीण इलाकों में भी अब बंद बॉडी वाले कचरा वाहनों से ही कचरे का परिवहन होगा। घनी आबादी वाले ग्रामीण और शहरी इलाकों में दिन में कम से कम दो बार सफाई करना अनिवार्य होगा। यदि किसी भी क्षेत्र में कचरे का अंबार मिला, तो संबंधित वार्ड प्रभारी और मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) पर सीधे गाज गिरेगी।

बजट का 30 फीसदी हिस्सा कचरा प्रबंधन पर होगा स्वाहा

प्रशासन ने अब वित्तीय चाबुक भी तैयार कर लिया है। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी और ग्रामीण) के तहत मिलने वाले कुल बजट का न्यूनतम 30 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ और सिर्फ अपशिष्ट प्रबंधन और रीसाइक्लिंग पर फूंकना होगा। अफसरों की लापरवाही को बेनकाब करने के लिए अब वार्ड स्तरीय रैंकिंग (स्वच्छता प्रतियोगिता) जारी होगी, जिससे यह साफ हो जाएगा कि कौन सा अधिकारी काम कर रहा है। नई कॉलोनियों में बिना वेस्ट हैंडलिंग ज़ोन के अनुमति नहीं मिलेगी। कलेक्टर की यह विशेष समिति अब रिड्यूस, रियूज और रिसाइकिल (कचरा घटाओ, पुनः उपयोग करो और पुनर्चक्रण करो) के मूल मंत्र पर काम करेगी। हर महीने इस सेल की समीक्षा बैठक होगी, जिसमें लापरवाही पाए जाने पर तत्काल निलंबन जैसी कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। देखना यह है कि यह नया सेल उमरिया को वाकई स्वच्छ बनाता है या फिर पुराने विभागों की तरह फाइलों में ही दफन होकर रह जाता है।

पीएम जनमन अंतर्गत उमरिया जिले के जनजातीय ग्रामों में संतृप्ति शिविरों का किया जा रहा आयोजन

उमरिया। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली तथा संचालनालय जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाएं, भोपाल के निर्देशानुसार पीएम जनमन एवं डीए-जेजीयूए अंतर्गत शामिल ग्रामों में विशेष लाभार्थी संतृप्ति शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों का उद्देश्य विशेष रूप से पीवीटीजी (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह) समुदायों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं से जोडऩा तथा उनके बीच जागरूकता बढ़ाना है। जनभागीदारी - सबसे दूर, सबसे पहले अभियान के तहत 25 मई 2026 तक राष्ट्रव्यापी सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में उमरिया जिले के करकेली, मानपुर एवं पाली विकासखंड के विभिन्न ग्रामों में शिविर आयोजित किए गए।

आयोजित शिविरों में ग्राम पंचायत सकरिया, अर्जुनी, कुरकुचा, उजान, घघराड, बरबसपुर, सरसवाही, बल्हौड़, बिजौरी, तामान्नारा ,बुढना,अंचला ताली, सलैया सहित अन्य ग्राम शामिल रहे। शिविरों में पहुंचे नोडल अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी देकर पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने की प्रक्रिया सुनिश्चित की।

शिविरों में जनजातीय समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन, आधार, पेंशन, आवास, आयुष्मान कार्ड एवं अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से जोडऩे के प्रयास किए गए। अधिकारियों ने ग्रामीणों से संवाद कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अधिकतम हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाने पर जोर दिया।

सिकल सेल एनीमिया जांच शिविर संपन्न, 86 मरीजों की हुई स्वास्थ्य जांच

हरिभूमि न्यूज कोतमा। स्वास्थ्य विभाग अनूपपुर एवं आयुष विभाग अनूपपुर तथा जन स्वास्थ्य सहयोग गनियारी के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा में एक दिवसीय सिकल सेल एनीमिया जांच शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर में सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित मरीजों की स्वास्थ्य जांच और परामर्श के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। शिविर के दौरान डॉ. संगीता प्रजापति द्वारा कुल 86 मरीजों की गहन जांच की गई। इस अवसर पर उन्होंने सिकल सेल एनीमिया के लक्षणों, बचाव और इसके प्रबंधन के बारे में उपस्थित मरीजों और उनके परिजनों को विस्तार से जानकारी दी। शिविर में मरीजों को आवश्यक एलोपैथिक और आयुर्वेदिक औषधियों का निःशुल्क वितरण किया गया। इसमें हाइड्रोक्सी यूरिया और फोलिक एसिड के साथ-साथ सहायक आयुर्वेदिक औषधियों जैसे अश्वगंधा चूर्ण, रास्ना सप्तक काढ़ा और च्यवनप्राश प्रमुख रूप से शामिल रहे। इस शिविर को सफल बनाने में खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. केएल दीवान का मार्गदर्शन एवं महत्वपूर्ण सहयोग रहा। शिविर के संचालन में जन स्वास्थ्य सहयोग, गनियारी संस्था की टीम की भूमिका

अत्यंत सराहनीय रही। इस अवसर पर श्रीमती वैभवी दुबे, पवन गुप्ता, पूजा मेहरा, शालिनी मिश्रा, ममता, सीमा सिंह, सीमा निराला, मालती मरावी और उमेश यादव सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। यह शिविर सिकल सेल एनीमिया के प्रति जागरूकता फैलाने और जरूरतमंद मरीजों तक उपचार पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा।

खाकी का खौफ खत्म या संरक्षण में फल-फूल रहा सट्टा-जुआ?

मोबाइल पर "एक का 90" का लालच, जंगलों में सज रही 52 परी की महफिल; मेहनतकशों की कमाई पर डाका, नवयुवक दलदल में फंसने का खतरा

धनपुरी। इन दिनों अवैध सट्टा और जुए के कारोबार को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। नगर के विभिन्न हिस्सों में मोबाइल फोन के जरिए कथित रूप से सट्टा खिलाए जाने की बातें सामने आ रही हैं, जहां लोगों को "एक का 90" मिलने का लालच देकर मेहनत की गाढ़ी कमाई दांव पर लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। क्षेत्र में चर्चा यह भी है कि इस पूरे खेल को संचालित करने वालों की जानकारी स्थानीय स्तर पर किसी से छिपी नहीं है, इसके बावजूद कार्रवाई के अभाव ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।स्थानीय नागरिकों का कहना है कि हालात ऐसे बन गए हैं कि सटोरियों और जुआड़ियों में खाकी वर्दी का खौफ कम होता दिखाई दे रहा है। लोगों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि आखिर लगातार चर्चाओं और शिकायतों के बावजूद अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन क्षेत्र में इसको लेकर चर्चा तेज है।

जानकारी के अनुसार बंगवार क्षेत्र के जंगलों में कथित रूप से जगह बदल-बदलकर जुए की फड़ संचालित किए जाने की बातें सामने आती रहती हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि सुनसान स्थानों पर देर रात तक ताश के पत्तों यानी "52 परी" का खेल चलता है, जहां कथित रूप से शराब और खानपान की भी व्यवस्था रहती है। जुआरियों द्वारा स्थान बदलते रहने की वजह से कार्रवाई कठिन होने की चर्चा भी क्षेत्र में है।सामाजिक जानकारों का कहना है कि सट्टा और जुए जैसी गतिविधियां केवल आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि परिवारों की शांति, युवाओं के भविष्य और सामाजिक वातावरण पर भी नकारात्मक असर डालती हैं। जल्दी पैसे कमाने की चाह में कई युवा इस दलदल की ओर आकर्षित हो सकते हैं, जिससे अपराध और आर्थिक अस्थिरता बढ़ने का खतरा रहता है।नगरवासियों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि संदिग्ध स्थानों पर नियमित गश्त बढ़ाई जाए, जंगल क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए तथा यदि कहीं अवैध सट्टा-जुआ संचालित हो रहा है तो संबंधित लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। लोगों का कहना है कि समय रहते प्रभावी कदम उठाए गए तो समाज को इस बुराई से बचाया जा सकता है और नवयुवकों को गलत राह पर जाने से रोका जा सकेगा।

पर्यावरण संरक्षण का संदेशः बुढार नगर परिषद अध्यक्ष और सीएमओ ने ई-रिक्शा से निर्माण कार्यों का निरीक्षण

बुढार। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगर परिषद ने एक अनूठी पहल की है। ईंधन की बचत और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने का संदेश लेकर नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती शालिनी सरावगी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी सौरभ श्रीवास्तव और स्थानीय पार्षदों ने ई-रिक्शा से नगर में चल रहे निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को स्वच्छ, हरित और ऊर्जा-संरक्षित बुढार बनाने के लिए प्रेरित करना था। नगर भ्रमण के दौरान अध्यक्ष और पार्षदों ने लोगों से अपील की कि वे प्रदूषण कम करने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करें।

महावीर गेट, नगर भवन औचक निरीक्षण

नगर भ्रमण के इसी सिलसिले में अध्यक्ष श्रीमती शालिनी सरावगी और सीएमओ सौरभ श्रीवास्तव ने पार्षदों के साथ महावीर गेट, नगर भवन का औचक निरीक्षण भी किया। रहमारा लक्ष्य बुढार को एक मॉडल टाउन बनाना है, जहाँ स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण हर नागरिक की जिम्मेदारी हो। ई-रिक्शा का उपयोग

कर हम समाज में यह संदेश देना चाहते हैं कि छोटे-छोटे प्रयासों से ही बड़ा बदलाव संभव है। निरीक्षण के दौरान पार्षद श्रीमती सविता सिंह, गीता प्रजापति, इंजीनियर सीपी पांडेय, संजय द्विवेदी उपस्थित रहे।

अमलाई ओसीएम की सड़क बनी 'खतरे की राह', हर दिन जान जोखिम में डालकर ड्यूटी पहुंच रहे कर्मचारी

2 किमी कच्चे रास्ते पर कोयला ट्रकों का दबाव, उड़ती धूल और बिना संकेतक डायवर्सन ने बढ़ाया हादसों का खतरा

धनपुरी। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के सोहागपुर क्षेत्र अंतर्गत अमलाई ओसीएम में कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आ रही है। अमलाई ओसीएम मेन गेट से सब एरिया कार्यालय तक लगभग दो किलोमीटर लंबी सड़क आज भी डामरीकरण का इंतजार कर रही है। प्रतिदिन सैकड़ों कर्मचारी टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर वाहनों से इसी मार्ग से ड्यूटी पर आते-जाते हैं, लेकिन सड़क की हालत अब कर्मचारियों के लिए बड़ी परेशानी और खतरे का कारण बन चुकी है।

जानकारी के अनुसार प्रबंधन द्वारा स्थायी डामर सड़क बनाने के बजाय खदानों की मिट्टी डालकर अस्थायी रूप से रास्ता तैयार कर दिया जाता है। इसी मार्ग से निजी कंपनियों के भारी कोयला लोड ट्रकों का लगातार आवागमन होता है। कच्ची सड़क पर जैसे ही बड़े वाहन गुजरते हैं, उनके पीछे धूल का गुबार और डस्ट का फव्वारा उठने लगता है। इससे पीछे चलने वाले छोटे वाहन चालक पूरी तरह धूल से नहा जाते हैं। कई बार धूल इतनी अधिक फैल जाती है कि सामने का रास्ता तक दिखाई नहीं देता, जिससे दुर्घटना की आशंका और बढ़ जाती है।

कर्मचारियों का कहना है कि सड़क पर पानी का

छिड़काव भी नियमित रूप से नहीं किया जाता। गर्मी और सूखे मौसम में हालात और अधिक खराब हो जाते हैं। धूल के कारण वाहन चालकों को आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी तक का सामना करना पड़ता है।

बिना संकेतक बदल दिया जाता है डायवर्सन

कर्मचारियों का आरोप है कि प्रबंधन समय-समय पर सड़क का डायवर्सन बदल देता है, लेकिन नए रास्तों पर कोई दिशा सूचक बोर्ड या चेतावनी संकेत नहीं लगाए जाते। परिणामस्वरूप कई बार कर्मचारी सब एरिया कार्यालय की बजाय खदान क्षेत्र की ओर पहुंच जाते हैं। रात के समय अंधेरा और धूल इस समस्या को और गंभीर बना देते हैं। स्थानीय कर्मचारियों ने मांग की है कि रोड पर रिफ्लेक्टर, सांकेतिक बोर्ड और लाल-हरी चेतावनी लाइट लगाई जाए, ताकि दूर से ही रास्ते की सही जानकारी मिल सके।

बरसात में बन जाती है जानलेवा सड़क

कच्ची सड़क बरसात के मौसम में कीचड़ और फिसलन से भर जाती है। पिछले वर्ष कई कर्मचारी इसी मार्ग पर फिसलकर घायल हो चुके हैं। दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह रास्ता सबसे अधिक खतरनाक माना जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि बारिश के दौरान ड्यूटी पर पहुंचना किसी जोखिम से कम नहीं होता।

अब जबकि मानसून आने में करीब 20 दिन का समय बचा है, अमलाई ओसीएम रोड की स्थिति कर्मचारियों की चिंता बढ़ा रही है। आरोप है कि प्रबंधन को पूरी जानकारी होने के बावजूद सड़क निर्माण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर पहल नहीं की जा रही।

करोड़ों का उत्पादन, लेकिन सड़क नहीं

स्थानीय लोगों और कर्मचारियों का कहना है कि अमलाई ओसीएम लाभ देने वाली खदानों में शामिल है। करोड़ों रुपए का उत्पादन देने वाली खदान में कर्मचारियों को सुरक्षित सड़क जैसी मूलभूत सुविधा तक उपलब्ध नहीं हो पाना कई सवाल खड़े करता है।

यदि समय रहते सड़क का डामरीकरण, नियमित पानी छिड़काव, संकेतक बोर्ड और सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए तो भविष्य में किसी बड़े हादसे से इंकार नहीं किया जा सकता। कर्मचारियों ने प्रबंधन से बरसात शुरू होने से पहले तत्काल सड़क निर्माण और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।

वर्षों से चल रहे ज़मीनी विवाद की गुत्थी कब सुलझा पायेगा राजस्व विभाग

शहडोल। जमीनी विवाद की गुत्थी सुलझाने में राजस्व विभाग को कई मामलों में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। जिले के जयसिंहनगर क्षेत्र के पटवारी हल्का बसोहरा क्रमांक 32 में प्रकाश में आया है, जहां बटांकन 111 के खसरा नंबर 111/5 रकवा 0.809 हेक्टेयर जो आवेदिका मेघईया पिता नरबदुआ यादव उम्र 76 वर्ष के नाम दर्ज है, जो उसे पिता के उत्तराधिकार पर प्राप्त हुआ है। वहीं खसरा नंबर 111/3 पर मिथिला प्रसाद गुप्ता पिता विशेषर गुप्ता रकवा 0.809 हेक्टेयर की भूमि है, जो उसे भी उत्तराधिकार पर प्राप्त हुआ है। आवेदिका ने जानकारी देते हुए बताया है कि संबंधित व्यक्ति ने दस्तावेजों में छेड़छाड़ कराकर खसरा क्र. 111/7 एवं 111/8 राजस्व के दस्तावेजों में दर्ज करा लिया है, ऐसे में आवेदिका मेघईया यादव सहित 111 बटांकन के पड़ोसी किसान भी वर्षों से परेशान हैं। कई बार सीमांकन हुए पर असलियत तक आज तक नहीं पहुंच सकी राजस्व विभाग की टीम, हालांकि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से विधिवत जांच की अपेक्षा की जा रही है। आवेदिका का कहना है कि यही कारण है कि वह और पड़ोसी किसान विगत कई वर्षों से अपने ज़मीनी दस्तावेज लेकर न्यायालय के चक्कर लगा रहे हैं किन्तु अब तक उन्हें संतोषजनक कार्यवाही का इंतजार है।

समय के साथ बढ़ता गया रकवा

आवेदिका ने जानकारी देते हुए बताया कि जब उसने नकल शाखा से दस्तावेज के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। तत्पश्चात उसे प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार मिथिला प्रसाद गुप्ता के पिता विशेषर गुप्ता के नाम खसरा नंबर 111/3 पर कुल 0.809 हेक्टेयर भूमि दर्ज मिली। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब संबंधित व्यक्ति को उसके पिता से उत्तराधिकार पर भूमि प्राप्त हुई तो उसका रकवा स्वतः कैसे बढ़ गया। पूर्व दस्तावेजों में जहां सन 1989-90 के पहले खसरा नंबर 111/7 और 111/8 का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता तो आखिर यह भूमि कहां से आयी। दूसरा सवाल यह है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा भूमि क्रय का भी कोई उल्लेख नहीं मिलता तो आखिर खसरे में भूमि का रकवा कैसे बढ़ा गया।

दस्तावेजों में छेड़छाड़ का आरोप

आवेदिका ने न्यायालय में कई बार यह आवेदन प्रस्तुत किया है कि बटांकन 111 के दस्तावेजों में छेड़छाड़ किया गया है जिस पर सुधार किया जाना न्यायसंगत होगा। जिसके बाद न्यायालय ने राजस्व प्रकरण क्र.-74/अ-3/2011-12 आदेश दिनांक 15-02-2013 को आदेश जारी करते हुए खसरा क्रमांक 111/5 पर छेड़छाड़ कर 111/8 प्रतीत होना बताया। जिस हेतु खसरे में संशोधन का आदेश जारी किए जाने का उल्लेख भी किया गया है। आवेदिका ने रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करने पर आरोपियों पर सख्त कार्यवाही करते हुए रिकॉर्ड सुधार की मांग भी की थी।

तत्कालीन पटवारी ने कर दिया तरमीम में संशोधन

आवेदिका ने तत्कालीन पटवारी बृजेन्द्र साकेत पर आरोप लगाते हुए कहा है कि राजस्व प्रकरण क्र.74/अ-3/2011-12 आदेश दिनांक 15-02-2013 के विरुद्ध मिथिला प्रसाद गुप्ता पिता विशेषर गुप्ता ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष तरमीम खारिज किए जाने की अपील प्रस्तुत की थी। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष प्रकरण विचाराधीन होने के बावजूद तत्कालीन पटवारी बृजेन्द्र साकेत ने संबंधित व्यक्ति से सांठ-गांठ कर पड़ोसी किसानों को सूचित किए बगैर मिथिला प्रसाद गुप्ता एवं उसके उत्तराधिकारियों के मनचाहे स्थान और आवेदिका के पट्टे आराजी की भूमि पर दोबारा तरमीम कर दी। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि प्रकरण विचाराधीन होने पर पटवारी ने किस आधार पर तरमीम कर दी। आवेदिका ने अनुविभागीय राजस्व के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर इसकी जानकारी देकर प्रकरण पर उचित कार्यवाही की मांग की है। आवेदिका ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आईएएस काजोल सिंह जो अपने निष्पक्ष निर्णय के लिए जानी जाती हैं, से अपील की है कि आवेदिका की अवस्था को दृष्टिगत रखते हुए उसे न्याय दिलाने की कार्यवाही की जाए।

खबर संक्षेप

प्राचीन पांडुलिपियों का ऐप में किया गया डिजिटल संरक्षण

अमरकंटक। प्राचीन पांडुलिपियाँ, ताडपत्र व दुर्लभ अभिलेखों के संरक्षण व भावी पीढ़ियों तक इनकी पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ज्ञान भारतम मिशन के तहत राष्ट्रीय पाण्डुलिपि सर्वे शुरू हो चुका है। देशभर में राष्ट्रीय पाण्डुलिपि सर्वेक्षण अभियान 16 मार्च से 15 जून तक संचालित किया जा रहा है। जिसमे जनभागीदारी के माध्यम से देशभर के परिवारों, मंदिरों एवं संस्थाओं में उपलब्ध पांडुलिपियों को ज्ञान भारतम ऐप के जरिये जिओ टैग कर सूचीबद्ध व डिजिटल रूप से संरक्षित किया जा रहा है। इसी अनुक्रम में धार्मिक नगरी एवं पर्यटन स्थल अमरकंटक के श्री कल्याण सेवा आश्रम के पुस्तकालय में उपलब्ध लगभग 166 प्राचीन पांडुलिपियों का अवलोकन कर उन्हें भारत ऐप में अपलोड करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। अभियान के तहत इन पांडुलिपियों को डिजिटल रूप से संरक्षित किया जा रहा है। इस दौरान मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड से पर्यटन प्रबंधक अजय अग्रवाल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जबलपुर मण्डल से आए जेएसए समरेश आनंद एवं श्री कल्याण सेवा आश्रम अमरकंटक के लाइब्रेरियन स्वामी सुन्दरानंद पुरी उपस्थित रहे। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन और अमूल्य पांडुलिपियों को डिजिटल फोर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए निःशुल्क प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, जिसके माध्यम से लोग अपने पास सुरक्षित पांडुलिपियों की जानकारी सरकार तक पहुंचा सकेंगे। उन्हें क्यूआर कोड स्कैन कर अपनी पाण्डुलिपि की डिटेल दर्ज करनी होगी। यदि किसी की पाण्डुलिपि की स्थिति ठीक नहीं है तो उसका संरक्षण (प्रिजर्वेशन) भी मंत्रालय की टीम करेगी। चिन्हित पांडुलिपियों को राष्ट्रीय डिजिटल रेपोजिटरी में सुरक्षित रखा जाएगा। इस अभियान में पाण्डुलिपि धारकों का स्वामित्व पूर्णतः सुरक्षित रहेगा। ऐप पर 23 भारतीय भाषाओं का विकल्प दिया गया है। इसमें व्यक्ति, संस्था, नागरिक और सर्वेयर जैसी प्रोफाइल चुनकर आवेदन किया जा सकेगा। ज्ञान भारतम अभियान के तहत लगभग 75 वर्ष या उससे अधिक पुरानी पांडुलिपियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस पहल से जिले की ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी।

जल जीवन मिशन कार्य में लापरवाही के आरोप

डिंडौरी न्यूज। करंजिया जनपद अंतर्गत ग्राम मोहतरा में जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपये की लागत से बनाए जा रहे फिल्टर प्लांट निर्माण कार्य में मजदूरों को पिछले दो माह से मजदूरी नहीं मिलने का मामला सामने आया है। निर्माण कार्य में लगे मजदूरों ने ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि लगातार काम कराने के बावजूद उन्हें समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट गहरा गया है।मजदूरों के अनुसार वे प्रतिदिन लगभग 15 किलोमीटर दूर-दराज क्षेत्रों से निर्माण स्थल तक पहुंचकर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दो महीने बीत जाने के बाद भी मजदूरी नहीं मिलने से परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो गया है। मजदूरों ने बताया कि कई बार ठेकेदार से भुगतान की मांग की गई, लेकिन हर बार केवल आश्वासन देकर मामला टाल दिया जाता है।

बिजुरी कांड में उठते सवाल

क्या सच छिपाने में जुटी है पुलिस या राजनीति चमकाने में कांग्रेस?

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। अनूपपुर जिले के बिजुरी में हुई हृदय विदारक घटना अब केवल एक आपराधिक मामला नहीं रह गई है, बल्कि पुलिस की कार्यशैली, जांच की पारदर्शिता और राजनीतिक सक्रियता पर बड़ा सवाल बन चुकी है। जिला कांग्रेस ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग तो की, लेकिन पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा उन सवालों की हो रही है जिन्हें अब तक पुलिस स्पष्ट नहीं कर पाई है। युवती की उम्र, मेडिकल परीक्षण, घटनास्थल के साक्ष्य और प्रेस नोट की विसंगतियां अब प्रशासनिक जवाबदेही को कठघरे में खड़ा कर रही हैं। बिजुरी की इस दर्दनाक घटना ने पूरे जिले को झकझोर दिया है। मगर जितनी तेजी से यह मामला जनता के बीच चर्चा का विषय बना, उतनी ही तेजी से पुलिस की कार्यवाही भी सवालों में घिर गई। कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन के जरिए पुलिस जांच को कठघरे में खड़ा करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी से ज्यादा ध्यान उन पत्रकारों और स्थानीय लोगों के सवालों पर है जिनका जवाब अब तक सामने नहीं आया। यदि पीड़िता वास्तव में नाबालिग थी तो पुलिस ने उसे 20 वर्षीय क्यों बताया? यदि शरीर से खून निकल रहा था तो उसका वैज्ञानिक परीक्षण क्यों नहीं हुआ? यदि संघर्ष के दौरान आरोपी के बाल हाथ में आने की बात कही गई तो डीएनए जांच की दिशा में कदम क्यों नहीं बढ़ाए गए? सबसे अहम सवाल यह कि बिना मेडिकल और फॉरेंसिक जांच पूरी हुए पुलिस इतनी जल्दी बलात्कार की संभावना को कैसे नकार सकती है? यही वे प्रश्न हैं जो अब कांग्रेस से ज्यादा पुलिस प्रशासन की विश्वसनीयता पर भारी पड़ रहे हैं।

उम्र का सच या पुलिस की जल्दबाजी?

पूरे मामले में सबसे बड़ा विवाद पीड़िता की उम्र को लेकर खड़ा हुआ है। पुलिस प्रेस नोट में युवती को 20 वर्षीय बताया गया, जबकि कांग्रेस नेताओं और परिजनों का दावा है कि वह 17 वर्ष की नाबालिग थी। सवाल यह उठता है कि आखिर पुलिस ने किस दस्तावेज के आधार पर उम्र तय कर दी? यदि बिना प्रमाण के प्रेस नोट जारी किया गया तो यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि जांच को प्रभावित करने की कोशिश भी मानी जा सकती है। पत्रकारों के बीच चर्चा है कि क्या उम्र बदलने से मामले की गंभीर धाराओं को कमजोर करने का प्रयास किया गया?

मेडिकल जांच से पहले बलात्कार की संभावना कैसे खारिज?

घटना के बाद सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय चर्चाओं तक गैंगरेप की आशंका जताई जा रही थी। परिजनों ने शरीर से खून निकलने और संघर्ष के निशान होने की बात कही, लेकिन पुलिस ने प्रेस नोट में बलात्कार की संभावना लगभग नकार दी। बड़ा सवाल यह है कि बिना विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट और वैज्ञानिक अनुसंधान के पुलिस इतनी निश्चित कैसे हो गई? क्या यह जांच का हिस्सा था या जल्दबाजी में कहानी गढ़ने की कोशिश? यही बिंदु अब पुलिस की निष्पक्षता पर सबसे बड़ा प्रश्नचिह्न बन गया है।

जिला कांग्रेस कमेटी

फरियादी या जांच का सबसे बड़ा किरदार?

जिस युवक को पुलिस फरियादी बता रही है, वही युवती को सुनसान स्थान पर लेकर गया था। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि उसका मेडिकल परीक्षण क्यों नहीं कराया गया? उसके कपड़े और अंतःवस्त्र जांच के लिए जब्त क्यों नहीं किए गए? यदि घटना इतनी गंभीर थी तो हर संभावित पहलू की निष्पक्ष जांच जरूरी थी। पत्रकारों के बीच यह चर्चा तेज है कि आखिर पुलिस किस आधार पर उसे केवल फरियादी मानकर चल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जांच की दिशा शुरू से तय कर दी गई थी?

घटनास्थल के साक्ष्यों पर पुलिस क्यों खामोश?

परिजनों का दावा है कि पीड़िता के हाथ में किसी आरोपी के बाल थे, जो संघर्ष का संकेत हो सकता है। यदि यह सच है तो यह बेहद महत्वपूर्ण साक्ष्य था। लेकिन पुलिस प्रेस नोट में इसका कोई उल्लेख नहीं मिला। यही नहीं, कथित मुंहबोले भाई के कपड़ों पर खून लगने की बात भी सामने आई, फिर भी पुलिस ने उसे सार्वजनिक जांच का हिस्सा नहीं बनाया। सवाल उठ रहा है कि क्या वैज्ञानिक अनुसंधान को जानबूझकर कमजोर किया गया या फिर जांच की गंभीरता ही नहीं समझी गई?

कांग्रेस की राजनीति या जनता के सवाल?

कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बड़ा हमला बोलते हुए थाना प्रभारी को हटाने और निष्पक्ष जांच की मांग की है। लेकिन राजनीतिक आक्रामकता के बीच असली केंद्र जनता और पत्रकारों के सवाल बन चुके हैं। यदि पुलिस की जांच पारदर्शी होती तो शायद विपक्ष को इतना बड़ा मुद्दा नहीं मिलता। प्रशासन के लिए चुनौती अब केवल आरोपियों तक पहुंचने की नहीं, बल्कि जनता का भरोसा बचाने की भी है। क्योंकि जब पुलिस के हर बयान पर संदेह होने लगे, तब मामला केवल अपराध नहीं बल्कि व्यवस्था के संकट में बदल जाता है।

अज्ञात वाहन से टकरा कर नर जंगली सूअर की मौत

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। जिला मुख्यालय से 9 किलोमीटर दूर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 43 भोलगढ गांव के समीप गुरुवार की शाम अज्ञात बड़े वाहन की ठोकर से एक जंगली सूअर के टकराने पर सूअर स्थल पर मृत हो गया, वनविभाग द्वारा मृत जंगली सूअर के प्रकरण पर कार्रवाई की है। गुरुवार की शाम राष्ट्रीय राज्य मार्ग 43 में ग्राम भोलगढ़ के पिंजरहा धार के समीप कुरियारी जंगल की ओर से रोड पर विचरण कर रहा एक जंगली सूअर अज्ञात वाहन से टकरा गया जिसकी स्थल पर ही मौत हो गई घटना की सूचना अनूपपुर से कोतमा की ओर जा रहे पत्रकार सुधाकर पयासी द्वारा वन्यजीव संरक्षक शशिधर अग्रवाल को दिए जाने पर श्री अग्रवाल द्वारा वन विभाग को सूचित करते हुए स्वयं घटना स्थल पर पहुंचकर भोलगढ वनरक्षक रोहित उपाध्याय एवं सुरक्षाश्रमिकों के साथ मृत जंगली सूअर के शव को वनचौकी भोलगढ़ में लाकर रखते हुए घटना की जानकारी वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को दिए जाने पर शुक्रवार के दिन डॉ, योगेश चंद्र दीक्षित पशु चिकित्सा अधिकारी अनूपपुर द्वारा पीएम की कार्यवाही किए जाने बाद वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में कफन, फूल एवं अगरबत्ती से मृत जंगली सूअर के शव का दाह संस्कार किया गया।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ बिलासपुर मंडल का विरोध प्रदर्शन संपन्न

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। रेलवे बोर्ड द्वारा 30000 पदों को सरेंडर किए जाने के निर्णय के विरोध में भारतीय रेलवे मजदूर संघ के आह्वान पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ बिलासपुर मंडल द्वारा दिनांक 15 मई से 29 मई तक शाखा स्तर, मंडल स्तर एवं जोन स्तर पर काला पट्टी बांधकर विरोध पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी क्रम में 22 मई को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय बिलासपुर के समक्ष विशाल विरोध प्रदर्शन एवं सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महामंत्री संतोष पटेल की विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम में वरिष्ठ जोनल सलाहकार निमाई बनर्जी, जोनल अध्यक्ष कमलेश सिंह, जोनल कार्यवाहक अध्यक्ष विवेकानंद चंद्रा, सहायक महामंत्री नूतन वर्मा एवं जोनल उपाध्यक्ष युवराज सिंह द्वारा मंच संचालन एवं सभा को संबोधित किया गया। यह विरोध प्रदर्शन जोनल सदस्य धर्मा राव, जोनल सदस्य राकेश पटेल एवं मंडल

अध्यक्ष राकेश साहू की अध्यक्षता तथा मंडल सचिव प्रोम्पी कुमार सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुआ। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने रेलवे प्रशासन की कर्मचारी विरोधी नीतियों की कड़ी आलोचना की तथा 30000 पदों को समाप्त करने के निर्णय को रेलवे एवं कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध बताया। वक्ताओं ने कहा कि लगातार पदों में कटौती से कर्मचारियों पर कार्यभार बढ़ रहा है, जिससे रेलवे की सुरक्षा, कार्यक्षमता एवं कर्मचारियों का मानसिक संतुलन प्रभावित हो रहा है। साथ ही सत्ताधारी यूनियन की निष्क्रियता एवं कर्मचारियों के मुद्दों पर उदासीन रवैये की भी आलोचना की गई। विरोध दिवस में संजय यादव सहायक मंडल सचिव, हरीश कुमार डहरवाल मंडल संगठन सचिव, उत्तम दास मानिकपुरी मंडल उपाध्यक्ष, संजय शर्मा शाखा सचिव मैकेनिकल, अरुण कुमार सहायक सचिव मैकेनिकल, शाखा सचिव अनूपपुर राजकमल पटेल, मिथिलेश यादव मंडल कार्यकारिणी सदस्य, मुख्य शाखा अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, रनिंग शाखा अध्यक्ष जेके वर्मा, विप्लव दास सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं कर्मचारी साथी उपस्थित रहे। अंत में मंडल रेल प्रबंधक को ज्ञापन सौंपकर उनके माध्यम से रेलवे बोर्ड अध्यक्ष को भेजा गया तथा कर्मचारियों के हित में 30000 पदों को सरेंडर करने के निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग की गई।

गो सम्मान अभियान के अंतर्गत संतों ने किया जनजागरण एवं सहभागिता का आह्वान

हरिभूमि न्यूज अमरकंटक। भारतीय संस्कृति, गो संरक्षण एवं जनजागरूकता को केंद्र में रखकर संचालित "गो सम्मान अभियान" के अंतर्गत देशव्यापी स्तर पर कार्यक्रमों एवं जनसंपर्क अभियान की घोषणा की गई है। अभियान के प्रचार-प्रसार हेतु जारी पत्रक में भारतीय परंपरा के अनुरूप गोवंश संरक्षण, संवर्धन तथा समाज में जागरूकता बढ़ाने को प्रमुख उद्देश्य बताया गया है। अभियान की कार्यकारिणी में प्रधान संरक्षक वेदलक्षणा गोमाता (आध्यात्मिक माँ सुदर्शनी) तथा अध्यक्ष नंदी बाबा (नीलमणि वृषभदेव) का उल्लेख किया गया है। अभियान को भारतीय परंपरा के आचार्यों, संतों एवं गोसेवा से जुड़े लोगों के सहयोग एवं आशीर्वाद का संदेश भी दिया गया है। अभियान के अंतर्गत मलूक पीठ वृंदावन धाम के शिष्य स्वामी विष्णु दास महाराज ने देशवासियों एवं गौभक्तों से अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक अपने-अपने तहसील, ब्लॉक, अनुभाग एवं मंडल अधिकारियों को ज्ञापन सौंपें तथा 27 जुलाई को जिला कलेक्टर के माध्यम से अपनी मांग शासन तक पहुंचाएं। साथ ही 27 अक्टूबर को राज्य सचिव के माध्यम से राज्यपाल एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किए जाएंगे तथा दिल्ली में एक विशाल कार्यक्रम आयोजित कर शासन से गौ माता के विषय में आवश्यक कार्रवाई की मांग की जाएगी। स्वामी विष्णु दास महाराज ने कहा कि गौ माता को सेवा, सुरक्षा और सम्मान मिलना चाहिए तथा इस दिशा में प्रभावी और समयबद्ध पहल आवश्यक है। इसी क्रम में गौ सम्मान अभियान के तहत स्वामी विष्णु दास महाराज ने अमरकंटक स्थित कल्याण सेवा आश्रम पहुंचकर आश्रम के प्रबंध न्यासी हिमाद्री मुनि महाराज एवं स्वामी जगदीशानंद महाराज से भेंट कर अभियान में सहभागी बनने का विनम्र अनुरोध किया। इस अवसर पर स्वामी धर्मानंद महाराज, स्वामी हरस्वरूप महाराज, स्वामी धुनी बाबा, राजेंद्र बिष्ट, रणजीत सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे तथा अभियान में सहभागिता दर्ज कराई। स्वामी विष्णु दास महाराज के साथ इस अवसर पर पंडित सुरेंद्र मिश्रा एवं पंडित राजेश तिवारी भी उपस्थित रहे। पत्रक में अभियान के प्रमुख उद्देश्यों में गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध, देशी गोवंश संरक्षण, गोसेवा हेतु प्रभावी व्यवस्था तथा गो आधारित कृषि एवं उत्पादों को प्रोत्साहन जैसे विषय शामिल किए गए हैं। अभियान से जुड़े लोगों के अनुसार इसका उद्देश्य भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों एवं गो संरक्षण के प्रति व्यापक जनजागरूकता विकसित करना है।

स्वच्छता रैली, विचार गोष्ठी, श्रमदान एवं पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित

हरिभूमि न्यूज अमरकंटक। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर 22 मई को वन परिक्षेत्र अमरकंटक के तत्वावधान में जनजागरूकता, स्वच्छता संदेश रैली, विचार गोष्ठी, माँ नर्मदा नदी के पावन तट पर श्रमदान स्वच्छता अभियान एवं पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम वनमंडलाधिकारी अनूपपुर एवं उप वनमंडलाधिकारी राजेंद्रग्राम के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अंतर्गत वन विद्यालय सभागार में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. रविन्द्र शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में ओजी गोस्वामी (सेवानिवृत्त उप वन संरक्षक/वन अनुविभागीय अधिकारी) उपस्थित रहे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता महेन्द्र कुमार यादव, सहायक अनुदेशक, वन विद्यालय अमरकंटक ने की। विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए डॉ. रविन्द्र शुक्ला ने जैव विविधता विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के साथ जल, जंगल एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संवर्धन वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। बदलते पर्यावरणीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए वृक्षों की कटाई रोकना तथा वृक्षारोपण को जनअभियान के रूप में अपनाना आवश्यक है। उन्होंने जैव विविधता के प्रकारों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रकृति की प्रत्येक इकाई मानव जीवन के लिए उपयोगी है तथा मधुमक्खी एवं तितली जैसे जीव पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओ.जी. गोस्वामी ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि वन्य जीवन का महत्व निरंतर बढ़ रहा है तथा पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए जीव-जंतुओं का संरक्षण मानव समाज की साझा जिम्मेदारी है। जैव विविधता समिति के अध्यक्ष धनंजय तिवारी ने कहा कि लगातार वन क्षेत्र घटने, बढ़ते तापमान एवं पर्यावरणीय बदलाव के कारण वन्य जीव प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मानव प्राकृतिक क्षेत्रों में अतिक्रमण कर रहा है जिससे वन्य प्राणी आबादी क्षेत्रों की ओर आने को विवश हो रहे हैं तथा संरक्षण के प्रति समाज को अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता का संदेश देते हुए जागरूकता रैली निकाली गई तथा माँ नर्मदा नदी के पावन तट पर श्रमदान कर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके साथ ही पौधरोपण कर जैव विविधता संरक्षण एवं पर्यावरण संवर्धन का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में पत्रकारों के रूप में श्रवण कुमार उपाध्याय, उमाशंकर पाण्डेय एवं धनंजय तिवारी उपस्थित रहे। वैद्यगण में गंगाधर, प्रदीप शुक्ला, के.डी. मानिकपुरी एवं भूषण सिंह शामिल रहे। समिति प्रतिनिधियों में जगत सिंह मरावी, गुलाब सिंह मरावी, रमेश सिंह मार्को, विनोद यादव, लालजी बघेल एवं जगजीवन सिंह (उप सरपंच, ग्राम पंचायत पोड़की) उपस्थित रहे। वन अमले की ओर से दशरथ प्रजापति (सहायक अनुदेशक, वन विद्यालय अमरकंटक), धनीराम रौतैल (कार्यप्रभारी वन परिक्षेत्राधिकारी अमरकंटक), जमुना सिंह मार्को (परिक्षेत्र सहायक भुंडाकोना), आलोक कुमार सिंह (परिक्षेत्र सहायक अमरकंटक) सहित वन परिक्षेत्र अमरकंटक एवं वन विद्यालय अमरकंटक के समस्त वन अमले तथा 67 वनरक्षक प्रशिक्षणार्थियों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। अंत में सभी उपस्थितजनों ने जैव विविधता संरक्षण, स्वच्छ पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन हेतु सामूहिक संकल्प लिया तथा कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

चौरा धाम जोगी तालाब में गूंजा जल संरक्षण का संकल्प सामूहिक श्रमदान से दिया जल बचाने का संदेश

बदरा/जमुना। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के निर्देशन एवं जिला समन्वयक के मार्गदर्शन में जल गंगा संवर्धन अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत विकासखंड अनूपपुर के सेक्टर क्रमांक-01 स्थित ग्राम पंचायत पयारी क्रमांक-1 के चौरा धाम जोगी तालाब घाट में सामूहिक श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रस्फुटन समितियों, सीएमसीएलडीपी छात्रों, महिलाओं एवं ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन का संदेश दिया। अभियान के दौरान तालाब परिसर एवं घाट क्षेत्र की साफ-सफाई की गई तथा जल स्रोतों के संरक्षण के लिए श्रमदान किया गया। उपस्थित लोगों ने तालाब क्षेत्र से गंदगी हटाकर स्वच्छ एवं सुरक्षित जल स्रोत बनाए रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को जल

संकट की चुनौती और उसके समाधान के लिए सामूहिक सहभागिता की आवश्यकता से अवगत कराया गया। इस अवसर पर जन अभियान परिषद अनूपपुर के जिला समन्वयक उमेश पांडे ने कहा कि जल संरक्षण केवल सरकारी योजनाओं का विषय नहीं बल्कि जनभागीदारी का अभियान है। उन्होंने सभी उपस्थित लोगों से श्रमदान की परंपरा को आगे बढ़ाने और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। नवांकुर संस्था के सचिव नागेंद्र सिंह ने बताया कि इस प्रकार के अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को कम करने, भूजल स्तर को बनाए रखने तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि समाज की सामूहिक भागीदारी से ही स्थायी विकास संभव है। कार्यक्रम के दौरान प्रस्फुटन समिति सदस्यों एवं सीएमसीएलडीपी छात्रों ने भी जल संरक्षण की आवश्यकता पर अपने विचार रखे और लोगों से दैनिक जीवन में जल बचत के उपाय अपनाने का आह्वान किया। अंत में परामर्शदाता शारदा चौरसिया द्वारा सभी प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया तथा जल संरक्षण एवं स्वच्छता के प्रति निरंतर जागरूक रहने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम स्थल पर "जल है तो कल है" जैसे नारों के साथ लोगों ने पर्यावरण संरक्षण का सामूहिक संकल्प भी लिया। कार्यक्रम में नवांकुर संस्था राम किशोर सिंह जन उत्थान समिति उरा, नगर विकास प्रस्फुटन समिति पसान, परामर्शदाता शिवानी सिंह, प्रस्फुटन समिति अनूपपुर, पयारी, दैखल, देवरी, बम्हनी, सीएमसीएलडीपी छात्र एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

नाम सुधार सूचना

मैं प्रकाश दास सोनवानी आयु 55 वर्ष पिता स्व. श्री चेतराम जाति पनिका निवासी-ग्राम किरगी, थाना राजेन्द्रग्राम, तहसील पुष्पराजगढ, जिला-अनूपपुर, म.प्र. का निवासी हूँ शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि मेरा आधार कार्ड नं. 834225005881 है। मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ। मेरे पुत्र राज पंकज सोनवानी के कक्षा 9 वीं, 10 वीं, 11 वीं, 12 वीं की परीक्षा पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय अमरकंटक विकास खण्ड पुष्पराजगढ जिला अनूपपुर म.प्र. से नियमित छात्र के रूप में अध्ययन कर उत्तीर्ण किया है। तथा मेरे पुत्र राज पंकज सोनवानी के कक्षा 9वीं, 10वीं, 11 वीं, 12 वीं, की मूल अंकसूची एवं टी. सी. में पिता का नाम प्रकाश सोनवानी दर्ज है मेरा सही व वास्तविक नाम प्रकाश दास सोनवानी है। मेरे पुत्र राज पंकज सोनवानी के कक्षा 8 वीं, 9 वीं, 10 वीं, 12 वीं की मूल अंकसूची एवं टी.सी. में मेरे नाम प्रकाश सोनवानी के स्थान पर सही नाम प्रकाश दास सोनवानी सुधार कराये जाने वास्ते उक्त शपथ निष्पादित कर रहा हूँ।